Names of the Countries
Netherlands
New Zealand
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russian Federation
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
United States of America

* 343. [The questioners (Shri Rajeev Shukla and Dr. Vijay Mallya) were absent. For answer *vide* page 34]

देश में कुष्ठ रोगी

344. **श्री मंगनी लाल मंडल:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विश्व भर के कुष्ठ रोगियों में से 62 प्रतिशत कुष्ठ रोगी हमारे देश में हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत में सर्वाधिक कुष्ठ रोगी बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार के द्वारा कुष्ठ रोग उन्मूलन अभियान चलाए जाने के बावजूद वर्तमान स्थिति में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस समय कुष्ठ रोगियों की संख्या क्या है और उनकी स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा॰ अन्बूमणि रामदास): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) एक जनवरी, 2005 को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में विश्व के कुल 286063 कुष्ठ रोगियों की तुलना में 216445 कुष्ठ रोगी थे। इस प्रकार भारत में विश्व के कुल कुष्ठ रोगियों का 75 प्रतिशत रोगी हैं।

(ख) इस समय भारत में सबसे अधिक संख्या में कुष्ठ रोगी बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हैं। इन राज्यों में देश की 42 प्रतिशत जनसंख्या है और कुल कुष्ठ रोगियों के 56 प्रतिशत रोगी हैं। तथापि, उपर्युक्त राज्यों में से मध्य प्रदेश में कुष्ठ की व्यापतता दर दिसम्बर, 2005 को 10,000 लोगों पर 0.87 थी और इस राज्य प्रदेश में कुष्ठ उन्मूलन का लक्ष्य (अर्थात् 10,000 लोगों पर एक से कम की व्यापतता दर) प्राप्त कर लिया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम की कार्यनीति और विषयवस्तु में काफी मात्रा में गुणवत्ता परिवर्तन हुए है।

1. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम पहले एक शीर्ष कार्यक्रम था जहां जनसंख्या के बहुत बड़े वर्गों तक कुष्ठ-सेवाएं अनुपलब्ध थीं।। वर्ष 2001-02 में इस कार्यक्रम को देश-भर में सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के साथ एकीकृत कर दिया गया। एकीकृत करने के पश्चात् देश भर में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सरकारी अस्पतालों में माध्यम से कुष्ठ निदान और उपचार सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं।
2. कुष्ठ के उपचार के लिए पहले केवल डोसोन औषध, उपलब्ध थी जिसकी कुष्ठ को ठीक करने की दर बहुत कम थी वर्ष 1982 में बहुऔषध चिकित्सा की शुरूआत से कुष्ठ का निश्चित इलाज उपलब्ध कराया गया था। अब कुष्ठ रोगियों का 6 महीने अथवा 12 महीने की अवधि के भीतर बहु-औषध चिकित्सा (एमडीटी) से सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि क्या रोगी मल्टी बेसिलरी अथवा पौसी बेसिलरी से ग्रस्त है।
3. पिछले वर्षों में कुष्ठ रोग को समाज में काफी हीन भावना से देखा जाता था। इस संबंध में सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण संबंधी प्रयासों को तेज करने के साथ-साथ कुष्ठ सेवाओं के एकीकरण से समाज में व्याप्त गलत धारण को दूर करने में सहायता मिली है और इससे इस रोग के बारे में अपने-आप सूचना देने वाले रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई जिससे रोगियों में समय उपचार करवाने की संभावना और विकलांगता दर में कमी आई है।

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कुष्ठ रोगों का निदान और उपचार करता है तथा इस चिकित्सा के पूरा होने पर उनको उपचार से मुक्त किया जाता है। 31 दिसम्बर, 2005 को देश ने 10,000 की जनसंख्या पर 0.95 रोगियों की व्यापतता दर सहित राष्ट्रीय स्तर पर कुष्ठ के उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। 31 जनवरी, 2006 को कुष्ठ रोगियों की राज्यवार सूची विवरण-I में दी गई है।

विवरण

31.1.2006 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत रोगी का पता लगाने, उसके उपचार और अस्पताल से छुट्टी देने के संबंध में स्थिति 2005-06

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	अनुमानित मध्य वर्ष जनसंख्या (2005-06)	3/05 तक दर्ज किए गए रोगी	पता लगाए गए नए रोगियों की संख्या		मास के अंत तक अस्पताल से छुट्टी दे दिए गए रोगियों की संख्या	मास के अंत तक रिकार्ड रोगी	प्रति 10.000 जनसंख्या पर व्याप्तता दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	80261156	6323	4101	2915	7016	8360	4979	0.62
2.	अरुणाचल प्रदेश	1210357	69	13	33	46	55	60	0.50
3.	असम	28776960	1182	314	736	1050	1074	1158	0.40
4.	बिहार	92626216	16532	13753	7550	21303	25574	12261	1.32
5.	छत्तीसगढ़	22395927	7994	3978	4042	8020	10824	5190	2.32
6.	गोवा	1430167	200	58	97	155	231	124	0.87
7.	गुजरात	55388820	3651	2706	2412	5118	4518	4251	0.77
8.	हरियाणा	23531510	423	108	188	296	289	430	0.18
9.	हिमाचल प्रदेश	6533220	241	49	134	183	223	201	0.31
10.	झारखंड	29536029	7823	3438	2778	6216	9914	4125	1.40
11.	जम्मू और कश्मीर	11279005	348	74	158	232	246	334	0.30
12.	कर्नाटक	56615219	4921	2112	2530	4642	5953	3610	0.64
13.	केरल	33148877	1282	491	453	944	1212	1014	0.31
14.	मध्य प्रदेश	66542897	6182	2319	3577	5896	6395	5683	0.85
15.	महाराष्ट्र	105962018	16513	6936	5073	12009	20595	7927	0.75
16.	मणिपुर	2684854	33	14	25	39	36	36	0.13
17.	मेघालय	2590912	42	6	6	12	27	27	0.10
18.	मिजोरम	998485	10	11	8	19	13	16	0.16
19.	नागालैंड	2474437	38	26	64	90	84	44	0.18
20.	उड़ीसा	39216761	8325	4115	3209	7324	10699	4950	1.26
21.	पंजाब	26320686	1047	376	622	998	909	1136	0.43
22.	राजस्थान	63087214	1996	211	943	1154	1581	1569	0.25
23.	सिक्किम	613412	26	13	9	22	24	24	0.39
24.	तमिलनाडु	65130045	5503	3627	2091	5718	7023	4198	0.64
25.	त्रिपुरा	3406339	47	23	43	66	30	83	0.24
26.	उत्तर प्रदेश	183956382	33884	17443	12647	30090	40745	23229	1.26
27.	उत्तरांचल	9172482	850	368	375	743	930	663	0.72
28.	पश्चिम बंगाल	86319826	18041	6563	6952	13515	19431	12125	1.40
29.	अ. और नि.द्वि. स.	396243	36	10	9	19	28	27	0.68
30.	चंडीगढ़	1046879	285	78	134	212	297	200	1.91
31.	दादरा और न.ह.	270550	66	98	45	143	145	64	2.37
32.	दमणदीव	192064	2	5	1	6	5	3	0.16
33.	दिल्ली	16311551	4958	1310	1779	3089	4602	3445	2.11
34.	लक्षद्वीप	65054	5	1	2	3	4	4	0.61
35.	पांडिचेरी	1058546	32	24	18	42	43	31	0.29
	कुल	1120551100	148910	174772	61658	136430	182119	103221	0.92

Leprosy patients in the country

†*344. SHRI MANGANI LAL MANDAL: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 62 per cent of the world's leprosy patients are in our country;

(b) whether it is also a fact that the largest number of such patients are there in Bihar, Uttar Pradesh, Orissa, Madhya Pradesh and West Bengal;

(c) whether there is no qualitative change in its present status despite the leprosy eradication programme of Government; and

(d) if so, the details of the existing number of Leprosy patients and their condition, State-wise and the details of action taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. ANBUMANI RAMDOSS): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) According to available data, as on 1st January 2005, India had 216445 cases of Leprosy as against the global total of 286063 cases, thus contributing 75% of the total cases globally.

(b) The State of Bihar, Uttar Pradesh, Orissa, Madhya Pradesh and West Bengal currently have the largest number of leprosy cases in India. These States contribute to 42% of country's population and have 56% of total leprosy cases. However of the above States, the prevalence rate of leprosy in Madhya Pradesh was 0.87/10,000 population as on December, 2005, and, thus, the State has already achieved elimination of leprosy (*i.e.* prevalence of less than 1/10,000 population).

(c) and (d) No, Sir, There are substantive qualitiative changes in the strategy and content of the National Leprosy Eradication Programme.

The National Leprosy Eradication Programme was previously a vertical programme where leprosy services were unavailable to large

segments of the population. In 2001-02, the programme was integrated with the General Health Care System throughout the country. After integration, leprosy diagnosis and treatment services are available through all Primary Health Centres and Government Hospitals throughout the country.

Earlier Dapsone was the only drug available for treatment of leprosy which had a very low cure rate. With the introduction of Multi Drug Therapy (MDT) in 1982, a definite cure for leprosy was made available, Now leprosy patients can be successuflly treated by MDT within a duration of 6 months or 12 months depending on whether the case is multi bacillary or pauci bacillary.

The Social stigma attached to leprosy was profound in previous years. Integration of leprosy services along with increased IEC efforts has helped to reduce the social stigma and has increased voluntary reporting resulting in timely treatment and reduction in disability rate.

The National Leprosy Eradication Programme diagnoses and treats leprosy patients and releases them from treatment on completion of the therapy. As on 31st December, 2005, the country has achieved elimination of leprosy at the national level with a prevalence of 0.95 cases/10,000 population. The State-wise list of leprosy cases as on 31st January, 2006, is given in Statement-I.

Statement-I

Status of cases detection, treatment & discharge under National Leprosy Eadication Programme as on 31.1.2006

Sl. No.	State/UT	Estimated Mid-year Population (2005-06)	Cases on record as on 3/05	No. of new cases detected			Cases discharged upto end of the month	Cases record at the end of month	Prevalence 10000 Population
				PB	MB	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Andhra Pradesh	80261156	6323	4101	2915	7016	8360	4979	0.62
2.	Arunachal Pradesh	1210357	69	13	33	46	55	60	0.50
3.	Assam	28776960	1182	314	736	1050	1074	1158	0.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Bihar	92626216	16532	13753	7550	21303	25574	12261	1.32
5.	Chhattisgarh	22395927	7994	3978	4042	8020	10824	5190	2.32
6.	Goa	1430167	200	58	97	155	231	124	0.87
7.	Gujarat	55388820	3651	2706	2412	5118	4518	4251	0.77
8.	Haryana	23531510	423	108	188	296	289	430	0.18
9.	Himachal Pradesh	6533220	241	49	134	183	223	201	0.31
10.	Jharkhand	29536029	7823	3438	2778	6216	9914	4125	1.40
11.	Jammu & Kashmir	11279005	348	74	158	232	246	334	0.30
12.	Karnataka	56615219	4921	2112	2530	4642	5953	3610	0.64
13.	Kerala	33148877	1282	491	453	944	1212	1014	0.31
14.	Madhya Pradesh	66542897	6182	2319	3577	5896	6395	5683	0.85
15.	Maharashtra	105962018	16513	6936	5073	12009	20595	7927	0.75
16.	Manipur	2684854	33	14	25	39	36	36	0.13
17.	Meghalaya	2590912	42	6	6	12	27	27	0.10
18.	Mizoram	998485	10	11	8	19	13	16	0.16
19.	Nagaland	2474437	38	26	64	90	84	44	0.18
20.	Orissa	39216761	8325	4115	3209	7324	10699	4950	1.26
21.	Punjab	26320686	1047	376	622	998	909	1136	0.43
22.	Rajasthan	63087214	1996	211	943	1154	1581	1569	0.25
23.	Sikkim	613412	26	13	9	22	24	24	0.39
24.	Tamil Nadu	65130045	5503	3627	2091	5718	7023	4198	0.64
25-	Tripura	3406339	47	23	43	66	30	83	0.24
26.	Uttar Pradesh	183956382	33884	17443	12647	30090	40745	23229	1.26
27.	Uttaranchal	9172482	850	368	375	743	930	663	0.72
28.	West Bengal	86319826	18041	6563	6952	13515	19431	12125	1.40
29.	A & N Islands	396243	36	10	9	19	28	27	0.68
30.	Chandigarh	1046879	285	78	134	212	297	200	1.91
31.	D & N Haveli	270550	66	98	45	143	145	64	2.37
32.	Daman & Diu	192064	2	5	1	6	5	3	0.16
33.	Delhi	16311551	4958	1310	1779	3089	4602	3445	2.11
34.	Lakshadweep	65054	5	1	2	3	4	4	0.61
35.	Pondicherry	1058546	32	24	18	42	43	31	0.29
	TOTAL:	1120551100	148910	174772	61658	136430	182119	103221	0.92

श्री मंगनी लाल मंडल: सभापति महोदय, सरकार ने स्वीकार किया है कि इस समय हिन्दुस्तान में कुछ प्रदेशों में कुल कुष्ठ रोगियों के 56 प्रतिशत रोगी हैं। इन प्रदेशों में स्थिति बड़ी भयावह है। इधर दिल्ली में भी यह संख्या प्रति 10 हजार 2.11 बताई गई है। इसी प्रकार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ दादर नागर हवेली में तो स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति रहने के बावजूद क्या सरकार ने 31 दिसंबर, 2005 को लेपरोसी का जो पीएलआर लेवल है एलिमिनेशन पर, उसकी कोई घोषणा की है? अगर घोषणा नहीं की है, तो जो स्थिति सरकार ने स्वयं बताई है, उस आलोक में इस देश में कुष्ठ रोगियों की स्थिति को निर्मूल करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है और दिशा में सघन रूप से क्या कार्यवाही की जा रही है?

DR. ANBUMANI RAMDOSS: Sir, before going to my answer, I would like to inform you and, through to the House that yesterday the Cabinet has cleared the proposal for six new AIIMS-like institutions. In fact, we are going to start the work very soon. Sir, it also covers upgrading elevent institutes in ten States.

Sir, coming to the answer, we have come a long way in the elimination and eradication of Leprosy in India, and, we all know that our Father of the Nation had been fighting for this cause. Sir, literally 70—75 per cent Leprosy patients in the world are from India, which is due to the sheer population of India. In December, 2005, India had announced that its has eliminated Leprosy. Elimination is bringing the prevalence rate to below one per ten thousand population, and, the WHO is on the terms of accepting this. This is a very big achievement and a big milestone. In the context that 75 per cent patients of Leprosy in the world are from India—literally, today, there are only six countries, Brazil, Madagascar, Mozambique, Congo, Tanzania and Nepal which have not even achieved the elimination rate—we have, in the last three to four years, done an extensive programme to achieve the elimination target which was fixed as December, 2005, and, we have achieved the target. Sir, we have come a long way.

Earlier, there was a National Leprosy Control Programme and we have modified that into National Leprosy Eradication Programme in 1983. And,

then, in the last 3-4 years, we have started Modified Leprosy Elimination Campaigns, called, MLEC campaigns, and, this was our main focus as we have now focussed on Districts and Blocks. Sir, we had taken up Districts with high prevalence, *i.e.*, with more than five per ten thousand of population, which were 72 Districts about 4-5 years ago, and, today we have reduced it literally to only two District which are high prevalence, *i.e.*, more than five per ten thousand of population. In fact, two Districts are from Delhi only. And, as the hon. Member knows, areas like Delhi, Chandigarh, Dadar and Nagar Haveli, have immigrant population. It is not like that Delhi has a high prevalence of Leprosy. All the population from surrounding areas come to Delhi for treatment, and, they are re-reported, misreported and a lot of other things happen.

We are very, very concerned and once we have achieved the elimination target, we are on the way to the eradication programme and there is not going to be any complacency because we have achieved the elimination target and we are very focussed. Today, Sir, 26 States have achieved the elimination target, that is below one per ten thousand of population. There are mainly six major States, and, we are now focussing on the block level. As I said, we have now Block Leprosy Awareness Campaigns. In fact, in the first campaign, we have covered about 836 blocks, and, in the second campaign, we have covered about 552 blocks. So, we are going at the root, and, definitely, we are doing our best.

श्री मंगनी लाल मंडल: महोदय, सरकार ने उत्तर दिया है और मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि ऐलिमिनेशन की घोषणा करने का जो स्तर है, वह कितने परसैंट है, क्योंकि WHO और ILEP, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एंअी लेप्रॉसी ऐसोसिएशन, दोनों का बड़ा योगदान है। महोदय, सरकार ने WHO और ILEP के साथ एक MoU दस्तखत किया है, तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार की घोषणा करने की जो नीति है और इन्होंने जो 31 दिसम्बर, 2005 को ऐलिमिनेशन की घोषणा की है, क्या इसमें WHO और ILEP की भी राय ली गई है, उन्होंने भी कोई अनुशंसा की है या यह सरकार का स्वयं का निर्णय है?

DR. ANBUMANI RAMDOSS: Sir, last year, on the first of January, we had about 2,16,000 cases of Leprosy. And this was WHO-authenticated. This year, as on 31st of January, we have about 1,03,000 cases. And, the WHO is authenticating these cases. They have their own means of surveillance. They are going to, in a few weeks or a few months, announce that. Sir, we have an MoU signed with the ILEP, the International

Federation of Anti Leprosy Association, whereby, in the next course, we are targeting re-constructive surgery to take out the stigma in the society. To eliminate that, a lot of IEC campaigns have been there. ILEP has signed an MoU with the Government of India, targeting these five major States, to take up the reconstructive surgery for the class II deformity, where they have the stigma and they are not able to work properly. So, we are now into that process, Sir. And, the WHO and the Government of India are closely coordinating on the mechanism. We are taking up the process.

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति जी, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि दुनिया में जो लेप्रोसी की बीमारी के शिकार हैं, उनकी जो संख्या 28,06,063 है और हिन्दुस्तान में इसकी संख्या 21,06,445 है, यानी इतनी अधिक संख्या में होने के बाद, अगर आप माननीय मंत्री जी के जवाब को देखेंगे तो इस साल के अंत में सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में 23,229 है। मेरा माननीय मंत्री जी से कहना है कि आपने डब्ल्यू०एच०ओ० के साथ में जो एम०ओ०यू० साइन किया है, सब कुछ किया है, लेकिन यदि यर्थात् के धरातल पर जाकर देखें तो जो लेप्रोसी के प्रेशेन्ट हैं, उनका सही ढंग से उपचार नहीं होता। हम कितनी ही बातें यहां पर कर लें, लेकिन जो संख्या दिखलाती है वह अत्यन्त ही भयानक संख्या है और इसकी रोकथाम के लिए हमें हर जिले के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था करनी होगी, जो एम०डी०टी० की गोलियां आपने बतलाई हैं, माननीय सभापति महोदय, मैंने अपने क्षेत्र में जाकर स्वयं देखा है कि उन मरीजों को बहुत मुश्किल से यह दवाइयां मिल पाती हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जिला अस्पताल में इस प्रकार की दवाइयां बराबर उपलब्ध रहें?

DR. ANBUMANI RAMDOSS: Sir, I have already informed that the number of cases this year, as on 31st January, is about 1,03,000. This was last year's figure. This has been authenticated by the WHO. The WHO authenticates and after that we will announce you the official figures, this year's January figures. Sir, like I have already said, we are now more focussed at the block level rather than the district level. In fact, we are going to the block level. We are having block leprosy awareness campaign. We had a modified leprosy awareness campaign, elimination campaign. We had five of them, right from 1998 till 2004. That was the one which literally focussed on the entire episode and we went house-to-house, door-to-door to identify this. We have taken up high prevalence blocks. In fact, we are now saying that in a matter of about five to six years, from 72 districts, it has come to only two districts, prevalence rate

of more than five per 10,000. And, I would like to deny that leprosy medicines are not available. They are available in abundance. In fact, we are going to them, we are going to the households. A lot of campaigns have been there. The IEC campaigns, Information, Education and Communications campaigns, have been conducted on this. And, if the hon. Member informs us where the medicines are not present, I will definitely take action against the concerned officials.

श्री तारिक अनवर: सभापति महोदय, मंत्री जी ने यह बताया है कि 'After integration, leprosy diagnosis and treatment services are available through all Primary Health Centres and Government Hospitals throughout the country'. तो जो हमारे प्राइमरी हैल्थ सेंटर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, उनकी स्थिति से हम सभी लोग वाकिफ हैं कि उसमें डाक्टर्स भी एवेलेबल नहीं रहते और दवा भी एवेलेबल नहीं है और यह बहुत ही गंभीर स्थिति का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि लेप्रोसी रिडक्शन के लिए सरकार ने कोई समय निर्धारित किया है या नहीं? कितने वर्षों में लेप्रोसी पूरी तरह से हमारे देश से समाप्त कर दी जाएगी और उसका क्या लक्ष्य है और क्या सरकार ने उसके लिए कोई समय निर्धारित किया है या सुनिश्चित किया है?

DR. ANBUMANI RAMDOSS: Sir, we all know that leprosy has a long incubation period. People don't come soon for treatment; they come only when they are completely affected by the disease. Even though the deformity rate was about 6.7 in 1994 (deformity is when hands get deformed), it has come down drastically to about 1.8 as of now because of early surveillance and early picking up the disease and treating that. Once these patients go under treatment, literally from the first week onwards, they don't spread any infection.

Sir, as I have already mentioned, we have achieved the elimination, and the next is eradication. Since all these problems are there and due to the stigma attached with this disease in the society, people don't come forward to claim that they have this problem. Now, we have started door-to-door campaign at block and district levels. My officers say that it will take minimum about 20 years to achieve the eradication rate. Sir, I don't want to deviate the House from this issue. But, like I said, we are not being complacent because we have achieved elimination rate. We are going all out, and it is the realistic figure because of the practical problem associated with this disease.

SHRIMATI N.P. DURGA: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether it is true that the second phase of the National Leprosy Elimination Project, which was started in April, 2000, was ended in March, 2004. If yes, whether the Ministry is thinking of restarting or extending the National Leprosy Elimination Project for three more years to eliminate leprosy, at least, by 2007. If yes, the details may be given. And if not, what are the reasons for not extending this Project?

DR. ANBUMANI RAMDOSS: Sir, we have only the Modified Leprosy Elimination Campaign. As I said, it started in 1998 till 2004 where blocks and districts were more focussed. Literally 836 blocks were covered initially. Then we came down to 552 blocks, which had the prevalence rate of more than two. Now, we are focussing on this. Now, we have gone into Block Leprosy Awareness Campaign. As I said, door-to-door service is an ongoing programme. We are selecting blocks which have high prevalence rates. That is an ongoing campaign in this programme.

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, from the answer of the hon. Minister, we have learnt that the problem is very huge in this country. I congratulate the Minister for his attempt to upgrade the status of about six hospitals in this country to the status of AIIMS. Sir, I want to know from the hon. Minister whether private corporate hospitals will be directed to treat leprosy patients. If already some of them are doing it, how many of them are treating leprosy patients?

DR. ANBUMANI RAMDOSS: Sir, as of now, leprosy drugs are given free of cost in all our Government centres. Lot of NGOs, which have been associated with the Government, and other agencies also are supporting this programme. If there are any private hospitals other than NGOs supplying, I will give the details to the hon. Members.

श्री कृपाल परमार: धन्यवाद सभापति महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 3 साल पहले कुष्ठ रोगियों की कुल संख्या के 62 फीसदी हिन्दुस्तान में थे और जब से सरकार ने इस बीमारी को निर्मूल करने का प्रण लिया है तब से इनकी संख्या बढ़कर 75 फीसदी हो गई है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जब से बहु औषधि चिकित्सा को अपनाया गया है, मल्टी ड्रग थैरेपी शुरू की गई है, उसके बाद 6 से 12 महीने के अंदर-अंदर रोगी ठीक हो जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर 6 से 12 महीने के अंदर रोगी ठीक हो जाता है और आप डोर टू डोर कैम्पेन करके रोगियों को ढूंढकर उनका इलाज कर रहे हैं, तो इनकी संख्या देश में क्यों बढ़ रही है?

DR. ANBUMANI RAMDOSS: Sir, the number has not increased. I have very clearly said that the number has decreased from last year.

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी जो व्यवस्था है, इसका टी॰वी॰ पर खूब प्रचार होता है, लेकिन टी॰वी॰ पर इस बात पर प्रचार नहीं होता है कि यह बीमारी छूआछूत की नहीं है। इसकी जितनी ज्यादा पब्लिसिटी होगी, उतने ही ज्यादा रोगी उपचार केन्द्रों पर जायेंगे और लोग भी उनके उपचार में सहयोग करेंगे। इसलिए आप इसकी पब्लिसिटी ज्यादा से ज्यादा करें।

DR. ANBUMANI RAMDOSS: Yes, Sir. I would like to thank you for the suggestion. We will take up the suggestion of creating awareness and publicity. Sir, like you said, there are two types of leprosy, multi-baccillary and pauci-baccillary. It takes treatment of about six months to twelve months. And when someone is put on treatment, literally, from the first day onwards, the transmission is not there. So, the bacteria doesn't spread literally. So, the drugs are very, very effective once the treatment starts. Today, we don't have any resistance to the drug. We haven't had any case also. Sir, we will take into consideration the suggestions in this regard.

MR. CHAIRMAN: Next Question No. 345.

Venture capital fund for dairy and poultry industry

*345. SHRIMATI MOHSINA KIDWAI:†
SHRI VIJAY J. DARDA:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have launched a new NABARD-sponsored venture capital fund for dairy and poultry industry with corpus of Rs. 25 crores for three years;

(b) if so, whether Government would ensure the provision of its micro-credit to individual entrepreneurs, unemployed youths, etc. percolates to tribals and other deprived sections of the society for their gainful employment; and

(c) whether the backward and tribal districts of Chhattisgarh and

† The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Mohsina Kidwai.